दबाव में पाकिस्तान

पुलवामा में सुरक्षाबलों पर आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई की और कूटनीतिक कदम उठाए हैं, उनका असर दिखने लगा है। पाकिस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर पर शिकंजा कसते हुए उसके बेटे और दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके अलावा और भी कई आतंकवादी संगठनों के आतंकी पकड़े गए हैं। स्पष्ट है कि भारत के रुख से पाकिस्तान सकते में है और भारी दबाव में भी। इसलिए उसे आतंकी संगठनों पर पाबंदी और आतंकियों की गिरफ्तारी जैसे कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा है। हो सकता है पहले की तरह पाकिस्तान यह कार्रवाई दिखावे के तौर पर कर रहा हो। भारत की संसद पर हमले के बाद भी 2001 में उसने जैश पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन वह आंखों में धूल झोंकने से ज्यादा कुछ नहीं था। हाफिज सईद को तीन बार नजरबंद किया, पठानकोट हमले के बाद मसूद अजहर को भी नजरबंद किया, लेकिन यह सब पाकिस्तान का ढोंग ही था।

पर आज हालात पहले से अलग हैं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से पाकिस्तानी सीमा में घुस कर जैश के ठिकानों को नष्ट किया, वह कड़ा संदेश है। पाकिस्तान अब यह बात अच्छी तरह से समझ गया है कि अगर उसने अभी भी अपने यहां पल रहे आतंकी संगठनों पर लगाम नहीं कसी तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त जो आतंकी संगठन हैं उनमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्करे-तैयबा और जमात-उद-दावा (जेयूडी) का दबदबा ज्यादा है। भारत में आतंकी हमलों में इन्हीं का हाथ रहा है। फिलहाल पाकिस्तान सरकार ने जैश, जेयूडी और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन पर नकेल कसी है। इन पर प्रतिबंध लगाने के बाद इनकी संपत्तियों और इनसे जुड़े मदरसों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। जमात-उद-दावा को अब तक धर्मार्थ कार्य चलाने वाला संगठन बताया जाता रहा है। जबकि हकीकत यह है कि इस संगठन की आड़ में वह भारत के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले आतंकी तैयार करता है। यह वक्त पाकिस्तान के लिए परीक्षा की घड़ी है, जब उसे साबित करना होगा कि वह अपने यहां से आतंकियों का नेटवर्क खत्म करने के लिए कृतसंकल्प है।

बेहतर होता कि पाकिस्तान सरकार आतंकियों के खिलाफ जो कदम उठाने को अब मजबूर हुई है, वह कई साल पहले ही उठाती। भारत ने संसद पर हमले, मुंबई हमले, फिर पठानकोट, उड़ी और नगरोटा में आतंकी हमलों के सारे विस्तृत और अकाट्य सबूत पाकिस्तान को दिए थे, लेकिन वह इन्हें खारिज करता रहा। पुलवामा हमले के बाद जो डॉजियर उसे दिया गया, उसमें भी मसूद के भाइयों के नाम थे। इस बार पाकिस्तान ने मसूद के भाई को पकड़ा है। इससे यह तो साबित हुआ है कि सारे वांछित आतंकी पाकिस्तान में हैं और सरकार, सेना, आइएसआइ सबको सारी जानकारी है। लेकिन इन्हें अब तक बचाया जा रहा था। पाकिस्तान के आतंरिक राज्यमंत्री शहरयार खान अफरीदी ने कुछ समय पहले कहा था कि जब तक उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ सत्ता में है, कोई भी जेहादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं सकता। जाहिर है, कौन आतंकियों को बना और बचा रहा है! पर अब पाकिस्तान बुरी तरह से घिर चुका है और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और उसके अपने मित्र चीन तक का दबाव है कि आतंकियों को खत्म करो। भारत लंबे समय से आतंकी हमलों के गुनहगारों को सौंपने की मांग करता रहा है। अब पाकिस्तान को चाहिए कि वह वांछित आतंकियों को भारत को सौंपे और अपने यहां चल रहे आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दुनिया के सामने इसके सबूत रखे।

मिलावट का रोग

इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि खाने-पीने की जो चीजें हमारे जिंदा और स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी हैं, वे भी मिलावट के कारोबारियों के स्वार्थों और अकूत मुनाफे की कमाई की मंशा की शिकार हैं और सरकारें ऐसा धंधा करने वालों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती हैं। यों मिलावटी सामान का भ्रष्ट और खतरनाक धंधा लंबे समय चल रहा है और इस पर चिंता जताने में हमारे सत्ता-संस्थानों ने कोई कमी नहीं की है। मगर सच यह है कि अब तक ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं हो सकी है जिसमें ऐसा अपराध करने वालों को पूरी तरह रोका जा सके। ताजा खबर राजस्थान से है जहां का स्वास्थ्य विभाग दालों, घी, बेसन, मावा, पनीर जैसी अन्य खाने-पीने की चीजों में हो रही मिलावट के धंधेबाजों के खिलाफ अभियान चला रहा है। मगर गिरफ्त में आ सके लोगों पर भी कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वजह यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सिर्फ जुर्माने के अलावा कोई सख्त कानूनी प्रावधान नहीं है। सवाल है कि इस कानूनी स्थिति के रहते मिलावट का कारोबार करने वालों को किस हद तक रोका जा सकेगा?

गौरतलब है कि राजस्थान में जमा किए गए खाद्य पदार्थों के करीब साढ़े इक्यावन हजार नमूनों में से साढ़े ग्यारह हजार से ज्यादा मिलावटी निकले। इनमें से भी करीब दो हजार नमूने मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक पाए गए। हालांकि इसके अलावा भी खाने-पीने की जितनी चीजें हैं, उनमें कोई मिलावट सेहत को किसी न किसी रूप में नुकसान ही पहुंचाएगी। राजस्थान में यह किसी तरह सरकारी दस्तावेज में दर्ज हो सकने वाली कार्रवाई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे इतर समूचे बाजार में लोगों को किस तरह का सामान खरीदना और उसका ही सेवन करना पड़ता है। यह किसी से छिपा नहीं है कि ज्यादातर लोगों को मिलावटी सामान की पहचान करने के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती और बाजार में उन्हें जो भी मिलता है, उसे ही वे अच्छा मान कर खाते-पीते हैं। उन्हें यह पता भी नहीं चल पाता है कि किस खाद्य पदार्थ के सेवन का उनकी सेहत पर कैसा असर पड़ता है। जबकि सच यह है कि जिस तरह का सामान हम आज खा-पी रहे हैं, उसमें कई में ऐसे घातक तत्त्व भी होते हैं जो लंबे समय में हमारी सेहत को जोखिम में डालते हैं। किसी बीमारी के इलाज की स्थिति में शायद ही कभी जांच का सिरा यह होता है कि क्या मरीज ने किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किया है, जो उसके रोग के लिए जिम्मेदार है!

सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की ओर से ऐसे अध्ययन अक्सर आते रहते हैं, जिनमें खाने-पीने की चीजों में मिलावट को लेकर चिंताजनक तथ्य दर्ज रहते हैं। लेकिन अब तक मिलावटखोरों के खिलाफ जैसे कानून हैं, उनके रहते इस कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाना मुमकिन नहीं है। फिलहाल मिलावटखोरों के लिए जो आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है भी, उसमें यह साबित करने की जरूरत पड़ती है कि मिलावटी पदार्थ की वजह से ही किसी व्यक्ति की मौत हुई है। जाहिर है, यह साबित करना एक जटिल काम है और यही वजह है कि इस कारोबार में लगे लोग आराम से अपने मुनाफे का धंधा करते रहते हैं। कायदे से अगर किसी खाद्य पदार्थ के सेवन से व्यक्ति बीमार हो जाता है या उसकी जान चली जाती है तो उस सामान को खुदरा विक्रेता से लेकर उसकी आपूर्ति करने से जुड़े नीचे से ऊपर तक के सभी लोगों को जिम्मेदार मान कर उनके लिए हत्या या हत्या के प्रयास जैसे कानूनों में दर्ज सख्त सजा की तरह का प्रावधान होना चाहिए।

कल्पमेधा

हम किसी पहाड़ को नहीं जीतते बल्कि
अपने आप पर विजय पाते हैं।
-एडमंड हिलेरी

ओआइसी, भारत और कूटनीति

संजीव पांडेय

ओआइसी के भीतर भी गहरी राजनीति है। भारत को इससे बचना होगा। इस संगठन के सदस्य देशों के बीच ही आपस में भारी विरोध हैं। कई देश तो एक-दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। उनकी आंतरिक राजनीति में पड़ना भारत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का जोरदार विरोध सुन्नी इस्लामिक देश कतर से है। ईरान और सऊदी अरब के बीच जंग तो जगजाहिर है।

बेशक यह खुश होने वाली खबर थी कि पहली बार इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआइसी) के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भारत की विदेश मंत्री विशेष निमंत्रण पर पहुंची थीं। पाकिस्तान इससे परेशान था। पाकिस्तान के पुराने मित्र सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों भारत को न बुलाने को लेकर पाकिस्तान के अड़ियल रवैये को मानने को तैयार नहीं थे। पाकिस्तान के आग्रह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। भारतीय विदेश मंत्री गईं, वहां उन्होंने इस्लामिक मुल्कों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। लेकिन इस बैठक की खासियत यह थी कि एशिया की बदलती परिस्थितियों में मेजबान ने न तो भारत को नाराज किया न पाकिस्तान को। कश्मीर मसले पर जहां पाकिस्तान फिर से भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाने में सफल रहा, वहीं भारत ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेरा।

अबु धाबी में इस्लामी सहयोग संगठन की बैठक तब हो रही थी जब भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर था। लेकिन मेजबान संयुक्त अरब अमीरात भारत को आमंत्रित कर चुका था। पाकिस्तान इससे काफी बौखलाया। लेकिन मेजबान देशों सहित इस्लामिक मुल्कों ने पाकिस्तान को बाद में खुश कर दिया। इस बैठक में इस्लामिक देशों ने साफ संकेत दिए कि फिलहाल भारत की कीमत पर वे पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहते। पाकिस्तान का महत्त्व अभी भी उनके लिए है। अबु धाबी में आयोजित इस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री का पहुंचना निश्चित तौर पर इस्लामिक देशों की कूटनीति में भारत की बड़ी सफलता था। लेकिन इस बैठक की समाप्ति के बाद पता चला कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अभी भी इस मंच से दुष्प्रचार करने में सफल रहा है। पाकिस्तान ने कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रस्ताव ही नहीं पारित करवाया, बल्कि भारत की जोरदार निंदा भी करवा दी। प्रस्ताव में भारतीय सेना की निंदा की गई थी और कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की मांग की गई थी। लेकिन इस मसले को मुख्य अबु धाबी घोषणा में शामिल नहीं किया गया। हालांकि इस्लामी सहयोग संगठन की बैठक में भारत को बुलाए जाने को लेकर पाकिस्तान भारी विरोध कर रहा था। पाकिस्तान में इस पर लगातार बहस हुई। पाकिस्तानी संसद में अपना पक्ष रखते हुए कई विपक्षी सांसदों ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री को बुलाए जाने को पाकिस्तान अपनी इज्जत का मसला न बनाए। इसमें पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वहां जाए और अपना पक्ष रखे।

भारतीय विदेश मंत्री ने इस मंच से आतंकवाद के खिलाफ जम कर बोला। यह निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि इसी मंच से पाकिस्तान लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा तो यह अखरा कि भारत को ओआइसी में न बुलाए जाने के उसके प्रस्ताव को संयुक्त अरब अमीरात के प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने ठुकरा दिया था। भारत को बुलाए जाने से नाराज पाकिस्तान शुरुआती बैठक में भी नहीं पहुंचा। पाकिस्तान का प्रस्ताव ठुकराए जाने के पीछे प्रिंस मोहम्मद बिन जायद और सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान की अहम भूमिका रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। दोनों राजकुमार निश्चित तौर पर पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर दोनों चिंतित हैं। आतंकवाद अब इन दोनों देशों के राजपरिवारों के लिए भी भारी चिंता का विषय है। इसलिए पाकिस्तान जो इस संगठन का संस्थापक देश है, उसके प्रस्ताव को उन्होंने नकार दिया। गौरतलब है कि इसी पाकिस्तान के विरोध के कारण ओआइसी की पहली बैठक में आमंत्रित भारतीय सदस्यों को बैठक में भाग लिए बिना वापस लौटना पड़ा था।

सुन्नी इस्लामिक देशों में भी आतंकवाद का भय समाया हुआ है। इसलिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की नीतियों में बदलाव आए हैं। हालांकि ये मुल्क लंबे समय से कट्टर इस्लाम को संरक्षण देते रहे हैं। पूरी दुनिया में आतंकवाद की जड़ बहावी इस्लाम को सऊदी अरब ने ही भारी संरक्षण दिया। लेकिन अब बहावी और कट्टर इस्लाम को संरक्षण देने वाले दोनों मुल्कों के राजपरिवारों को इस विचारधारा से खतरा महसूस हो रहा है। इन राजपरिवारों की सत्ता को उखाड़ने के लिए आतंकी

संगठनों ने ही नहीं मुसलिम ब्रदरहुड ने भी काफी लंबे समय से आंदोलन चला रखा है। कुछ अफ्रीकी देशों में सत्ता परिवर्तन को लेकर सफल आंदोलन चलाने वाले मुसलिम ब्रदरहुड का मुख्य निशाना एशियाई इस्लामिक देश हैं, जिनमें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं। मुसलिम ब्रदरहुड लगातार एशिया के मुसलिम देशों में तख्तापलट की कोशिश कर रहा है। इससे दोनों मुल्कों के राजपरिवार डरे हुए हैं। वहीं एशिया में शिया बहुल ईरान पहले से ही सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के लिए सरदर्द बना हुआ है। यही कारण है कि सऊदी अरब के राजकुमार प्रिंस मोहम्मद सलमान अब बहावी इस्लाम की बजाए वास्तविक इस्लाम की बात करने लगे हैं। इन मुल्कों की नीतियों में इन बदलावों के कारण भारत इनके नजदीक आया है। सऊदी अरब और यूएई नहीं चाहते कि आर्थिक रूप से ताकतवर होता भारत ईरान के ज्यादा नजदीक हो जाए। कई सुन्नी इस्लामिक मुल्क इस सच्चाई को जानते हैं कि पाकिस्तान की सैन्य शक्ति और भूगोल इस्लामिक मुल्कों के लिए महत्त्वपूर्ण है। पर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन कई इस्लामिक देशों के लिए भी बड़ा खतरा हैं। पेट्रोलियम और गैस के संसाधनों से युक्त सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भारत की आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोनों मुल्कों को भारत में ऊर्जा का बड़ा बाजार दिख रहा है। इससे भी पाकिस्तान की परेशानी बढ़ रही है।

ओआइसी के भीतर भी गहरी राजनीति है। भारत को इससे बचना होगा। इस संगठन के सदस्य देशों के बीच ही आपस में भारी विरोध हैं। कई देश तो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। उनकी आंतरिक राजनीति में पड़ना भारत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का जोरदार विरोध सुन्नी इस्लामिक देश कतर से है। ईरान और सऊदी अरब के बीच जंग तो जगजाहिर है। दोनों मुल्क यमन में एक-दूसरे के सामने सैन्य टकराव में हैं। दोनों के बीच शिया-सुन्नी विवाद भी तनाव का बड़ा कारण है। दिलचस्प तो यह है कि ओआइसी की बैठक में जब भी इस्लामिक देशों के भीतर शिया या सुन्नी अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की बात उठती है तो कोई हल नहीं निकलता। ईरान में सुन्नी मुसलमानों और सऊदी अरब में शिया अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मसला लगातार उठता रहा है। लेकिन इस्लामिक सहयोग संगठन इसे हल करने में विफल रहा है। पाकिस्तान में भी शिया आबादी का उत्पीड़न किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान सरकार इन सुन्नी आतंकी संगठनों की मदद करती रही है। लेकिन इस्लामिक सहयोग संगठन चुप रहा है।

भारत को खास सतर्क रहने की जरूरत इसलिए भी है कि मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान ईरान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। भारत को इस बैठक में बुला कर वे भारत को इस्लामिक दुनिया की आंतरिक राजनीति में भी इस्तेमाल करना चाहेंगे। वे चाहते हैं कि भारत ईरान से दूरी बनाए। पर भारत के लिए ईरान से दूरी बनाना खतरनाक होगा, क्योंकि भारत का चाबहार में भारी निवेश है। ईरान भारत के लिए अफगानिस्तान में जाने का रास्ता भी दे रहा है। इसलिए सुन्नी इस्लामिक मुल्कों की राजनीति और कूटनीति दोनों को भारत को समझना होगा।

शिकायत का हासिल

आलोक रंजन

दुनिया मेरे आगे

पुरस्कार प्राप्त करते हुए वह वाकई खूबसूरत लग रही थी। सोशल मीडिया पर जब उसने तस्वीर डाली, तभी से सब उसे बधाई दे रहे थे। मैंने बधाई के साथ-साथ उसके सुंदर लगने वाली बात भी लिखी। थोड़े दिनों बाद हम किसी मुद्दे पर बात कर रहे थे और बात आगे चली तो उस टिप्पणी पर पहुंच गई। साथ में उसने यह भी जोड़ा कि उसका जिक्र आते ही मैं सौंदर्य से जुड़ी बातें करता हूं जो उसे अच्छी नहीं लगतीं। ऐसा नहीं था कि उसे सुंदर होना अच्छा नहीं लगता, बल्कि बात उससे आगे की थी। उसने जो कहा वह एक साथ बहुत कुछ सिखाने वाला और लंबे समय से चली आ रही मेरी मान्यताओं को बदल देने वाला साबित हुआ।

उसका कहना था कि किसी के सौंदर्य पर बात करना उतना जरूरी नहीं है, जितना कि उसके प्रयास और उसकी मेहनत पर। बात सौंदर्य पर केंद्रित होकर रह जाती है और उसके पीछे वह सब छिप जाता है जो किसी इंसान के लिए आवश्यक है। मसलन, मेहनत और उसका आत्मविश्वास आदि। लड़कियों के मामले में यह बात बहुत आसानी से दिख जाती है। उनके सारे काम पीछे रह जाते हैं और उनकी हर सफलता उनके रूप के इर्द-गिर्द सिमट कर रह जाती है। यह स्त्री को सीमित और छोटा कर देने वाली प्रक्रिया है। बात स्त्री तक इसलिए आ गई कि साधारणतया कोई भी पुरुष किसी पुरुष के रूप की प्रशंसा नहीं करता, उसे सुंदर नहीं कहता। जब वह कह रही थी, तब तो नहीं, लेकिन उसके कुछ देर बाद उसकी बात वाजिब लगी। उसकी शिकायत सौ प्रतिशत जरूरी लगी।

मैंने एकाध बार को छोड़ कर शायद ही कभी किसी पुरुष की तस्वीर पर 'बहुत सुंदर' कहा होगा! उस दिन समझ में आया कि मेरा किसी को सुंदर कहना कितना जेंडर आधारित है! एक पुरुष के रूप में जाने-अनजाने मेरी जो ट्रेनिंग हुई, वह भी इसी बात की रही। समाज लगातार अपनी भाषा में, अपने कृत्य में यह सिखाता चला गया कि सुंदर का प्रयोग विपरीत लिंग के प्रति किया जाए। थोड़ा सोचने पर यह बात खुल गई कि समान लिंगीय के रूप की प्रशंसा करने पर उसे हतोत्साहित करने के भी प्रयास किए जाते हैं। मुझे अपनी एक और दोस्त की बातचीत याद आई। मैंने उसके पति के शारीरिक सौंदर्य की तारीफ की। उसने तुरंत मुझे कहा- 'तुम्हारा इरादा क्या है।' मुझे वहां पर अपनी बात स्पष्ट करनी पड़ी। निश्चित रूप से वह एक मजाक था, लेकिन मेरी दोस्त ने उस मान्यता को ही आगे बढ़ाने वाला कार्य किया, जिसमें सौंदर्य की प्रशंसा लिंग-निरपेक्ष नहीं रहती।

स्त्री द्वारा किए गए काम और उसकी सफलता को एक व्यक्ति के काम या उसकी सफलता की दृष्टि से देखे जाने से पहले उसके सौंदर्य के अनुपात में देखा जाता है। यों तो यह एक सार्वभौमिक सत्य है, लेकिन भारत के समाज में इसे काफी आसानी से देखा जा सकता है। स्त्री को उपभोग की दृष्टि से देखने की हमारी मानसिकता ने स्त्री को बराबरी से देखना सिखाया ही नहीं। इसलिए उसकी सफलता को कम करके देखने की प्रवृत्ति हमेशा से रही। स्त्री का सुंदर होना सबसे पहले नजर आया। कभी-कभी उसका स्त्री होना ही पर्याप्त रहा। सोशल मीडिया पर इसे आसानी देखा जा सकता है। एक ही विषय पर स्त्री और पुरुष की एक समान टिप्पणी होने पर भी जनमत पुरुष की प्रतिक्रिया की ओर साफ झुका हुआ दिखता है। स्त्रियों के हिस्से उनकी तस्वीरों पर आए हुए 'लाइक्स' ही आते हैं। यह सब कहना एक सामान्यीकरण लग सकता है, लेकिन वर्तमान दौर में यही सच है।

उसकी शिकायत से समझ आया कि स्त्री को बार-बार सुंदर कहना उसकी प्रशंसा नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व की समग्रता का बार-बार अस्वीकार है। यह कुछ ऐसी बात हुई कि कभी उसमें सुंदरता के अतिरिक्त कुछ और दिखा ही नहीं। उसकी जी-तोड़ मेहनत नहीं दिखी, उसका अपने काम के प्रति समर्पण नहीं दिखा। अगर उसने एक पुरस्कार प्राप्त किया तो उस पुरस्कार के मिलने से पहले उसने अपने समकक्षों में से अव्वल आने लायक काम किया होगा जो खुली प्रतियोगिता के दौर में आसानी से संभव नहीं। फिलहाल हम जिस सामाजिक ढांचे में रहते हैं, उसमें सत्ता की हैसियत में पुरुष है और उसी ने प्रतियोगिता के मानक रचे हैं तो वह आमतौर पर पुरुषों के हक में जाता है। इसमें एक स्त्री को जगह बनाने के लिए पुरुषों के मुकाबले ज्यादा बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

ऐसी स्थिति में बधाई देते हुए उसके सौंदर्य पर की गई बात बड़ी लज्जास्पद जान पड़ती है। मैं उस शिकायत को एक सीख की तरह लेता हूं, जिसने यह समझ दी कि सुंदर होना व्यक्ति के हाथ में नहीं है। अगर प्रशंसा करनी ही है तो व्यक्ति के प्रयासों की करनी चाहिए, जिसमें व्यक्ति की भूमिका साफ दिखती है। नैन-नक्श का आकर्षक होना आनुवांशिक है, लेकिन इंसान की मेहनत उसकी अपनी। अगर कोई लड़की सफल होती है तो उसकी मेहनत और काम को देखने समझने की जरूरत है।

शहादत और सियासत

वायुसेना प्रमुख के जवाब ने बयानवीर नेताओं को एक तरह से बेइज्जत कर दिया। सवाल पूछा गया था कि पाकिस्तान में किए गए हवाई हमले में कितने आतंकी मारे गए? उनका सीधा जवाब था- 'कितने टारगेट हिट करने हैं हम ये देखते हैं, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है।'

पिछले दिनों कुछ नेता लाशें गिनने में जुटे थे। एक गुट वाले नेता लाशें गिन कर नंबर बढ़ा रहे थे ताकि सीटें उसी अनुपात में बढ़ जाएं तो दूसरे गुट वाले उस कैलकुलेटर का पता मांग रहे थे जिस पर लाशों की संख्या का कुल योग निकाला गया था ताकि पहले गुट की सीटें घटा सकें! हद दर्जे का तमाशा चल रहा है देश में! अरे भाई, तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लाशों की गिनती नहीं बताई गई थी..तो क्यों इसमें उलझे पड़े हैं? जो सेना का काम है, जो विदेश मंत्रालय का काम है, जो रक्षा मंत्रालय का काम है, उसमें ये राजनीतिक दलों के नेता क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? कितना मजाकिया लग रहा है कि एक कह रहा है साढ़े तीन सौ, दूसरा ढाई सौ, तीसरा पूछ रहा है किसने कहा, कैसे पता? चौथा कह रहा है- फोटो, वीडियो तो दिखवा दो...! और इससे भी ज्यादा मजाकिया यह लगता है कि दोनों ही गुट एक-दूसरे को कह रहे हैं कि वे देशहित पर राजनीति न करें!

दूसरी तरफ नेताओं के देशप्रेम का आलम यह है कि बेगूसराय के शहीद पिंटू सिंह के पार्थिव शरीर के साथ पूरा शहर सड़कों पर उमड़ा हुआ था मगर बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक गांधी मैदान में चुनावी रैली में व्यस्त थे। ठीक है कि नेताओं का असली प्रेम राजनीति, चुनाव, वोट ही होता है और यह सोच रही होगी कि शहादतें तो होती ही रहती हैं, चुनाव तो पांच साल में एक बार ही आते हैं लिहाजा पहले इसी को तवज्जो दी जाए! लेकिन कम से कम एक मंत्री को तो सरकार का प्रतिनिधि बना कर शहीद पिंटू सिंह के अंतिम संस्कार में भेजा ही जा सकता था। यह बेहद अफसोसनाक है कि जिस मंच से बिहार के शहीदों को प्रधानमंत्री ने नाम ले-लेकर नमन किया, उसी मंच पर मौजूद बिहार के एक भी मंत्री को यह खयाल तक नहीं आया कि शहीद पिंटू सिंह की अंत्येष्टि में भी जाकर हाजिरी ही लगवा आता। यहां गांधी मैदान की हाजिरी ज्यादा जरूरी महसूस की गई!

यह बेहद दुखद है कि हमारे देश के नेता, चाहे वे किसी भी दल के हों, चुनाव और सत्ता से आगे इनकी सोच जा ही नहीं पाती, जबकि यह वक्त देश को सर्वोपरि रखने का है। सेनाओं का मनोबल क्या जुबानी भाषण से बढ़ेगा, जब शहीद का परिवार देखे कि जिसने अपने प्राणों का बलिदान देश के लिए दिया, उसके लिए देश तो छोड़िए, राज्य की सरकार के एक भी मंत्री तक को अंतिम विदाई में जाने की भी फुर्सत नहीं है।

● *मो. ताबिश, जामिया मिल्लिया, नई दिल्ली*

राज्यों को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली सहित कई शहर जहरीली गैस के चेंबर बन चुके हैं। प्रदूषण के बाबत आए दिन नए-नए तथ्य और आंकड़े भयानक तस्वीर पेश कर रहे हैं। अगले पांच सालों में वायु प्रदूषण को तीस फीसद तक कम करना एक बड़ी चुनौती है। इसकी वजह यह है कि पहले ही इस काम में काफी देर हो चुकी है और प्रदूषण बढ़ने की रफ्तार उठाए जाने वाले कदमों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। प्रदूषण से निपटने के लिए जन भागीदारी भी बहुत जरूरी है। जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, सरकार के प्रयास बेकार साबित होंगे।

● *चांद मोहम्मद, आंबेडकर कॉलेज, दिल्ली*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

भ्रष्टाचार का रोग

आजादी के सात दशक बाद भी भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या के रूप में देश में मौजूद है। कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रह गया है। यह एक दीमक की तरह भारतीय तंत्र की जड़ें खोखली कर रहा है। नौबत यह है कि बड़ी संख्या में लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए रिश्वतखोरी का सहारा लेते हैं। विडंबना यह कि हम इसके खात्मे के उपाय ढूंढ़ने के बजाय एक-दूसरे को दोष देते रहते हैं। अगर समय रहते भ्रष्टाचार के खिलाफ कारगर कदम नहीं उठाए गए तो देश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

● *श्रीनिवास पंवार बिश्नोई, माडिया, राजस्थान*

आतंक पर नकेल

पाकिस्तान के आतंकवाद को विश्व के सामने लाने के प्रयासों में भारत को अभूतपूर्व सफलता मिली है। भारत के अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को साधने का ही नतीजा रहा कि पाकिस्तान शेष विश्व से लगभग अलग-थलग पड़ गया है। इसी कूटनीति दबाव के चलते उसे भारत के एक पायलट को लगभग चौबीस घंटे में ही बिना शर्त रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा है। सारा विश्व जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है और पिछले दो-तीन दशकों से वह इस्लामिक आतंकवाद का सिरमौर बना बैठा है।

यह सही है कि अमेरिका ने ही अफगानिस्तान में सोवियत संघ की मौजूदगी के खिलाफ पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री स्थापित करने में मदद की थी। जब उसी फैक्ट्री से फल-फूल कर अनेक फैक्ट्रियां बन गईं और वे स्वयं अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो गईं तब अमेरिका को अपनी भूल का अहसास हुआ। भारत पिछले चालीस वर्षों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित है। पुलवामा हमले के बाद पैदा हालात ने भारत को सहनशीलता का चोला उतार फेंकने पर मजबूर कर दिया और भारतीय वायु सेना ने बालाकोट में कार्रवाई करके पाकिस्तान को उसकी करनी का फल चखा दिया। कंधार कांड या मुंबई हमले के बाद अगर ऐसी कार्रवाई हो गई होती तो भारत को शायद आतंकवाद के इतने दंश न झेलने पड़ते। हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे पाकिस्तान-पोषित आतंकवाद पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी, लेकिन भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध जो आक्रामक नीति अपनाई है, उसे नए युग की शुरुआत समझा जाना चाहिए और इसके सुखद परिणाम अवश्य आएंगे।

● *सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, नई दिल्ली*